



2026:AHC:22625-DB

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2096/1984

सती दीन व अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : राम बहादुर, रमेश प्रजापति, एस.के. श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता, उप शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह,

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार,

(माननीय चांद धारी सिंह, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया)

- वर्तमान आपराधिक अपील हमीरपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 15/1983 में दिनांक 27.07.1984 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अभियुक्त-अपीलकर्ताओं, अर्थात् सती दीन और धानी राम उर्फ धनाइयां द्वारा दायर की गई है, जिसमें न्यायाधीश ने दोनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
- दिनांक 21.04.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 04.10.2016 की कार्यालय रिपोर्ट पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता संख्या 1, अर्थात् सती दीन के संबंध में आपराधिक अपील को समाप्त कर दिया।

संक्षिप्त तथ्य

- संक्षेप में, वर्तमान आपराधिक अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि 9 अगस्त 1982 को राजा भैया पुत्र मनवोधन, निवासी ग्राम भुवसी, पुलिस थाना- मौदाहा, जिला- हमीरपुर ने प्रभारी निरीक्षक, पुलिस थाना-मौदाहा, जिला-हमीरपुर को एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि वे (शिकायतकर्ता) और उनके बड़े भाई गुणुवा (जिसे आगे "मृतक" कहा गया है) तालाब से पानी भरकर घर लौट रहे थे। मृतक शिकायतकर्ता से आगे चल रहा था। तभी बंदूक से लैस माइकू, आरोपी-अपीलकर्ताओं सती दीन और धानी राम के साथ बाहर आया। सती दीन के पास भाला (बल्लम) था, जबकि धानी राम के पास कुल्हाड़ी (फरसा) थी। सती दीन और धानी राम ने माइकू को गुणुवा को जान से मारने के लिए "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उकसाया क्योंकि गुणुवा ने एक बार उसकी पिस्तौल जब्त करवा ली थी और उसकी छह बीघा जमीन भी छीन ली थी। पुरानी दुश्मनी के चलते, माइकू ने मृतक के पीछे से आकर उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। गोली मृतक की पीठ में लगी, जिससे वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मुखबिर की चीख और गोली चलने की आवाज सुनकर रामा, करेलाल, मुकांदो और परमा घटनास्थल की ओर दौड़े और बीच-बचाव करने की कोशिश की। आरोपी पूर्व दिशा की ओर भाग गए। घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद हुआ।

4. उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट (प्रदर्शित दस्तावेज क-1) के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मामला संख्या 140/1982 दर्ज किया गया, पुलिस स्टेशन- मौदाहा, जिला- हमीरपुर।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, कानून ने कार्रवाई शुरू की और मामले की जांच अभियोजन पक्ष के गवाह-5, सब इंस्पेक्टर करुणा शंकर शुक्ला को सौंपी गई। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 9 अगस्त 1982 को उन्हें इस मामले की जांच सौंपी गई थी। वे मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर रवाना हुए, लेकिन बारिश के कारण वे टोला गांव में ही रुक गए। 8 अगस्त 1982 को सुबह 10:00 बजे वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक का शव पड़ा था। कांस्टेबल विजय सिंह, सूचना देने वाले राजा भैया, श्रीमती किदाया (मृतक की पत्नी) और गांव के कई अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया और फोटो लाश और चालान लाश तैयार किए, जिन्हें उन्होंने प्रमाणित किया और क्रमशः प्रदर्शित दस्तावेज क-3 और प्रदर्शित दस्तावेज क- 5 के रूप में दर्ज किया गया। मृतक के शव को सील करके कांस्टेबल पूरन चंद्र शर्मा और कांस्टेबल विजय सिंह द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद, उन्होंने मुखबिर राजा भैया और गवाहों करेलाल और परमा के बयान दर्ज किए। उन्होंने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया, जिसे प्रदर्शित दस्तावेज क-6 के रूप में दर्ज किया गया। रक्त से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी को अलग-अलग बक्सों में इकट्ठा करके सील कर दिया गया, जिसे प्रदर्शित क-7 के रूप में दर्ज किया गया। रक्त से सने छर्रे भी बरामद किए गए, जिन्हें कब्जे में लेकर प्रदर्शित क- 8 के रूप में दर्ज किया गया। घटनास्थल से एक खाली कारतूस और एक मिट्टी का बर्तन भी कब्जे में लिया गया, जिन्हें सील करके क्रमशः प्रदर्शित क-9 और प्रदर्शित क-10 के रूप में दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की गई लेकिन वे नहीं मिले। 12.08.1982 को कांस्टेबल कन्हैयालाल और कांस्टेबल विजय सिंह (गवाह-2) के बयान दर्ज किए गए। 18.08.1982 को उन्हें सूचना मिली कि आरोपी-अपीलकर्ता धानी राम उर्फ धनाइयां ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। 29.08.1982 को आरोपी माइकू की संपत्ति कुर्क कर ली गई। 10.09.1982 को गवाहों, रमा और मुकुंदी के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने जांच के गवाहों के बयान भी दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद, उन्होंने 10.09.1982 को आरोपपत्र दाखिल किया, जिसे दस्तावेज संख्या 11 के रूप में चिह्नित किया गया।

6. हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी थी, जिसे दस्तावेज संख्या 12 के रूप में चिह्नित किया गया था। उक्त चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को रिपोर्ट संख्या 12 दिनांक 09.08.1982 को दोपहर 12:15 बजे सामान्य डायरी में दर्ज किया गया था, जिसे प्रदर्शित क-13 के रूप में चिह्नित किया गया था। मालखाना से लाए गए दो बक्सों और एक धोती वाले सीलबंद बंडल को देखकर उन्होंने बताया कि ये वे दो बक्से हैं जिनमें खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी को कब्जे में लिया गया था और उक्त धोती मृतक द्वारा पहनी गई थी। उक्त धोती को सामग्री प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि दोनों बक्सों को सामग्री प्रदर्श II और III के रूप में चिह्नित किया गया था। दो अन्य सीलबंद

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पैकेटों को देखते हुए, उन्होंने बताया कि एक पैकेट में खाली कारतूस हैं, जिसे साक्ष्य संख्या IV के रूप में चिह्नित किया गया है, जबकि दूसरे में छर्रे हैं, जिसे साक्ष्य संख्या V के रूप में चिह्नित किया गया है। घटना स्थल से बरामद सामग्री 10.08.1982 को पुलिस स्टेशन में प्रस्तुत की गई।

7. चूंकि यह मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए माननीय मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां मामला सत्र परीक्षण संख्या 15/1983 के रूप में पंजीकृत किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर ने दिनांक 26.04.1983 के आदेश द्वारा आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 302 के साथ धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए आरोप तय किए, जिन्हें आरोपी-अपीलकर्ताओं को हिंदी में पढ़कर समझाया गया, जिन्होंने दोषी नहीं होने का दावा किया और सुनवाई की मांग की।

8. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के अपराध को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पाँच गवाहों की गवाही ली है, जिनमें प्रथम गवाह राजा भैया (सूचनादाता/तथ्य गवाह), द्वितीय गवाह कांस्टेबल विजय सिंह, तृतीय गवाह रमा (तथ्य गवाह), चतुर्थ गवाह दया शंकर (एक्स-रे तकनीशियन) और पंचम गवाह सहायक जांचकर्ता करुणा शंकर शुक्ला शामिल हैं।

9. अभियोजन पक्ष का प्रथम गवाह राजा भैया, जो मृतक के भाई और मुख्य सूचनादाता हैं, ने 20.12.1983 को दर्ज अपने प्रारंभिक बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए विवरण को दोहराया है। उन्होंने आगे बताया कि दोनों अभियुक्त-अपीलकर्ता सती दीन और धानी राम उर्फ धनाइयां सगे भाई हैं और दोनों उनके ही गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता सती दीन मृतक की ओर दौड़ा और भाले से उसकी छाती पर वार किया।

10. अभियोजन पक्ष का गवाह-2 कांस्टेबल विजय सिंह ने अपने मुख्य बयान में गवाही दी है कि शव की जांच के बाद, उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ कपड़े में सील कर दिया गया था। 10.08.1982 को उन्हें कांस्टेबल पूरन चंद्र शर्मा के साथ जिला अस्पताल हमीरपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर ने 11.08.1982 को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया।

11. अभियोजन पक्ष का गवाह-3 रमा ने अपने मुख्य बयान में, जो 22.12.1983 को दर्ज किया गया था, गवाही दी है कि वह आरोपी-अपीलकर्ताओं को अच्छी तरह से जानता है, जो सगे भाई हैं। वह आरोपी माइकू को भी जानता था, जो घटना के बाद से फरार है। माइकू सती दीन का बेटा है। वह मृतक को अच्छी तरह जानता था। मृतक की हत्या लगभग सवा वर्ष पहले हुई थी।

12. अभियोजन पक्ष का गवाह-4 दया शंकर, एक्स-रे तकनीशियन, ने अपने बयान में कहा कि 11.08.1982 को डॉ. एम.यू. खान ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने की। हाल ही में डॉ. एम.यू. खान का विदेश तबादला हो गया है और निकट भविष्य में उनके लौटने की कोई संभावना नहीं है।

13. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाई गईं:-

1. बाएं कंधे के निचले कोण क्षेत्र में 4 सेमी x 4 सेमी x गुहा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की गहराई x का प्रवेश घाव। घाव के किनारे के आसपास कालापन मौजूद है। दिशा बाएं निप्पल के निकट बाईं ओर छाती पर थोड़ा ऊपर और आगे की ओर है। चोट के पास की पांचवीं और छठी पसलियां टूटी हुई हैं।

2. बाएं निप्पल के निकट 3 सेमी की दूरी पर छाती के बाईं ओर 3 बजे की स्थिति पर 1 सेमी x 1 सेमी x गोलाकार का निकास घाव, जो चोट संख्या 1 से जुड़ा हुआ है।

3. गोली लगने से हुआ घाव, निकास द्वार 1-1/2 सेमी x 1 सेमी x अंडाकार 4-1/2 सेमी, बाएं निप्पल से मेडिकल दिशा में और चोट संख्या 2 से 1 सेमी नीचे, चोट संख्या 1 से जुड़ा हुआ।

4. गोली लगने से हुआ घाव, निकास द्वार 1-1/2 सेमी x 1 सेमी x अंडाकार 6 सेमी, बाएं निप्पल से मेडिकल दिशा में और चोट संख्या 3 से 1-1/2 सेमी नीचे, चोट संख्या 1 से जुड़ा हुआ।

5. छेद वाला घाव, 1/2 सेमी x 1/2 सेमी x गहरा गड्ढा, बाएं तरफ छाती में, बाएं निप्पल से 8 सेमी नीचे, 5 बजे की स्थिति पर। घाव की दिशा आगे से पीछे की ओर और थोड़ा ऊपर की ओर थी। बाईं ओर की तीसरी पसली आगे की ओर टूटी हुई है। फेफड़े का बायां ऊपरी और मध्य भाग और पूरा हृदय फटा हुआ है।

14. आंतरिक जांच करने पर, फुफ्फुस झिल्ली बाईं ओर फटी हुई पाई गई, बायां फेफड़ा बुरी तरह से फटा हुआ था, हृदय की बाहरी परत फटी हुई थी और हृदय के सभी कक्ष फटे हुए थे। पेट खाली था और आंत में मल और गैस मौजूद थीं।

15. डॉक्टर की राय में, मृतक की मृत्यु उक्त पूर्व-मृत्यु चोटों के कारण हुए आघात और रक्तस्राव से हुई थी।

16. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं सती दीन और धानी राम उर्फ धनैयन के बयान धारा 313 दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के तहत दर्ज किए गए, जिन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।

17. माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर ने पक्षों के अधिवक्ताओं की सुनवाई करने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का आकलन, मूल्यांकन और जांच करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

18. अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ताओं का निवेदन

19. श्री अनिल श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री राम बहादुर, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने की, ने पुरजोर तर्क दिया कि अपीलकर्ता लगभग 100 वर्ष की आयु का एक शतायु व्यक्ति

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



है। आगे उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता भी दुर्बल और कमजोर है और अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ है। यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता को केवल उपदेश देने का कार्य सौंपा गया था। मुख्य आरोपी माइकू, जिसने मृतक को गोली मारकर घायल किया है, को पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया है। मृतक के शरीर पर लगी चोट संख्या 5 के संबंध में, यह आरोपी-अपीलकर्ता सती दीन द्वारा भाले से मारी गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष का गवाह-1 राजा भैया ने अपने बयान में कहा है। अपीलकर्ता धानी राम उर्फ धनाइयां कुल्हाड़ी से लैस था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, कुल्हाड़ी से कोई चोट नहीं आई थी। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका साबित करने में विफल रहा है।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता का निवेदन

20. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एन. तिवारी ने इस आपराधिक अपील का विरोध करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते और सजा सुनाते समय कोई त्रुटि या गैरकानूनी कार्य नहीं किया है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी-अपीलकर्ता अब 100 वर्ष के हैं।

विश्लेषण और निष्कर्ष

21. हमने आरोपी-अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव और उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एन. तिवारी की दलीलें सुनीं। हमने अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया।

22. अपीलकर्ता ने उपरोक्त दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए यह आपराधिक अपील दायर की। संबंधित पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुबह लगभग 10 बजे, जब मुखबिर (गवाह-1) अपने साथी गुणुवा (मृतक) के साथ टंकी से पानी भरकर घर लौट रहा था और जब वह माइकू के कमरे के पास से गुजरा, तो आरोपी माइकू और सह-आरोपी सती दीन और धानी राम उर्फ धनाइयां उस कमरे से बाहर आए। उस समय, आरोपी माइकू के पास बंदूक थी, जबकि धानी राम उर्फ धनाइयां के पास फरसा और सती दीन के पास बल्लम (एक प्रकार का हथियार) था। आरोपी सती दीन और धानी राम उर्फ धनाइयां ने आरोपी माइकू को गुनावा को जान से मारने के लिए उकसाया, जिसके बाद माइकू ने गुनावा के पीछे पहुंचकर उस पर गोली चला दी।

23. अभियोजन पक्ष के गवाह-1 राजा भैया ने अपनी जिरह में बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग सुबह 11 बजे लिखी गई थी और उन्होंने उसी स्याही से उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था जिससे शिव चरण ने इसे लिखा था। हालांकि, अंगूठे के निशान की स्याही गहरे नीले रंग की है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने वाली स्याही नीले-काले रंग की है। गवाह-3 रमा ने अपनी जिरह में बताया कि वह लगभग दो घंटे तक घटनास्थल पर मौजूद रहे। उनके वहां रहने के दौरान, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शित का.1) लिखने वाले शिव चरण वहां नहीं पहुंचे थे। उपरोक्त विरोधाभासों को देखते हुए, हमारा मानना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जांच अधिकारी के आने के बाद उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई होगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



24. चिकित्सा साक्ष्य गवाहों द्वारा दिए गए बयान से भिन्न है। चोट संख्या 5 मृतक के शरीर पर बाईं ओर छाती पर एक छेदा हुआ घाव था, जो आगे से पीछे की ओर और थोड़ा ऊपर की ओर था। इसकी दिशा को देखते हुए, यह संभव नहीं है कि मृतक के जमीन पर गिरने के दौरान यह घाव लगा हो। अभियोजन पक्ष का गवाह 1 राजा भैया और अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या 3 रमा ने बताया है कि मृतक गुणुवा जमीन पर मुंह के बल गिरा था। मृतक का शव उसी स्थिति में पड़ा था। रमा (गवाह संख्या 3) के अनुसार, आरोपी सती दीन ने गोली लगने से घायल होने के बाद जमीन पर गिरने पर उसके सीने में भाले/बल्लम से वार किया था। उपरोक्त चर्चा/अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, यह संभव नहीं है कि इस स्थिति में ये चोटें लगी हों।

25. अभियोजन पक्ष का गवाह संख्या 1 ने अपनी जिरह में बताया कि इस घटना से पहले उसके एक अन्य भाई दीवान की भी हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के मामले में आरोपी जय करण, लालाई और जगदेव को दोषी ठहराया गया था और मृतक गुणुवा उनके खिलाफ गवाह था। उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोपियों को इस घटना से लगभग 4-5 साल पहले उनकी सजा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया था। गवाह संख्या 3 (रामा) ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि मृतक गुणुवा की हत्या जयकरण आदि ने की हो। राजा भैया (गवाह संख्या 1) ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि मृतक गुणुवा की केवल एक ही बेटी थी जिसका नाम कौसी था और उन्होंने इस तथ्य के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की कि वह अपनी संपत्ति अपनी बेटी कौसी को देना चाहते थे। रामा (गवाह संख्या 3) ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि गुणुवा की जमीन उन्हें विरासत में मिली थी और गुणुवा जीवित रहते हुए कहते थे कि वह अपनी मृत्यु के बाद अपनी जमीन अपनी बेटी को दे देंगे। इसलिए इस मामले में इन गवाहों द्वारा अपीलकर्ता को झूठा फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा उक्त अपराध करने के पीछे का मकसद भी साबित नहीं हुआ है।

26. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह है कि क्या उपर्युक्त दो गवाहों की गवाही के आधार पर अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, जो परस्पर विरोधी और अविश्वसनीय तथ्यों से भरी हुई थी, कानून की दृष्टि से मान्य हो सकती है।

27. सर्वोच्च न्यायालय ने वदिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य¹ मामले में गवाहों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

- (i) पूर्णतः विश्वसनीय
- (ii) पूर्णतः अविश्वसनीय
- (iii) न पूर्णतः विश्वसनीय और न पूर्णतः अविश्वसनीय।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कानून साक्ष्य की गुणवत्ता से संबंधित है, न कि उसकी मात्रा से। किसी एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि वह पूर्णतः विश्वसनीय पाई जाती है। इसके विपरीत, यदि कोई गवाह पूर्णतः अविश्वसनीय पाया जाता है, तो उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। तीसरी श्रेणी में आने वाले गवाहों के मामले में, न्यायालय को उनकी गवाही पर कार्रवाई करने से पहले महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए।

28. हमने उपर्युक्त दो प्रमुख गवाहों के साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और कई कारणों से उनके बयानों को मौलिक रूप से अविश्वसनीय पाया है:

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (i) घटना के क्रम में विरोधाभास।
- (ii) प्रत्यक्षदर्शी के लिए अशोभनीय आचरण।
- (iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट में चूक।
- (iv) अंतर्निहित असंभावनाएँ।

29. पंकज बनाम राजस्थान राज्य² मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जब घटना की उत्पत्ति और तरीका संदिग्ध हो, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसने भगवान सहाय बनाम राजस्थान राज्य³ मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा घटना की उत्पत्ति को छुपाने का दोषी पाया जाता है, तो संदेह का लाभ देना ही एकमात्र उचित उपाय है।

30. कन्नाड्या बनाम मध्य प्रदेश राज्य⁴ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के एक दोषसिद्धि को रद्द कर दिया क्योंकि चश्मदीदों ने अपराध स्थल और उपस्थित लोगों की मीटिंग के संबंध में विरोधाभासी विवरण दिए थे। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे विरोधाभासी विवरण एक विश्वसनीय विवरण के अंतर्गत नहीं आ सकते।

31. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम) की धारा 3 के अनुसार वैधानिक रूप से आवश्यक साक्ष्य का मानक "संभावना की प्रबलता" है। धारा 3 में उचित "संदेह से परे साक्ष्य" के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, हालांकि भारत में किसी आपराधिक मामले में आवश्यक साक्ष्य का स्तर "संभावना की प्रबलता" से अधिक होता है। साक्ष्य की प्रबलता को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 1891 (छठा संक्षिप्त संस्करण, 1991) में संक्षेप में इस प्रकार समझाया गया है:

"साक्ष्य की प्रबलता वह साक्ष्य है जो इसके विरोध में प्रस्तुत साक्ष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण या अधिक ठोस हो; अर्थात्, वह साक्ष्य जो समग्र रूप से यह दर्शाता है कि सिद्ध किए जाने वाले तथ्य की संभावना अधिक है।"

"सिद्ध" शब्द का अर्थ है कि किसी तथ्य को सिद्ध तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार करने के बाद या तो उसके अस्तित्व में विश्वास करता है, या उसके साक्ष्य को इतना संभावित मानता है कि मामले की परिस्थितियों में एक विवेकशील व्यक्ति को उसके अस्तित्व की धारणा पर कार्य करना चाहिए। किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए किसी निर्णायक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें शामिल प्रक्रिया संभावनाओं का आकलन करना है। अतः "संभावना की प्रबलता" दीवानी मामलों में निर्णय का आधार होती है। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अभाव में भी, जो आपराधिक मामलों में निर्णय के लिए किसी उच्च स्तर के प्रमाण को निर्धारित करती है, भारत में "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आपराधिक न्यायालय ऐसे प्रमाण के स्तर पर जोर देते रहे हैं जो दीवानी मामलों में निर्णय के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक है।

32. हमने इंग्लैंड के सामान्य कानून का अनुसरण किया है, जहाँ आपराधिक न्यायालय आपराधिक मामलों का निर्णय करते समय साक्ष्य के ऐसे स्तर पर जोर देते हैं जो निश्चित रूप से दीवानी मामलों का निर्णय करने के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक होता है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी, उनके साक्ष्य अधिनियम में आपराधिक मामले का निर्णय करने के लिए साक्ष्य के किसी उच्च स्तर का प्रावधान नहीं है। लेकिन समय के साथ, कई न्यायिक निर्णयों ने उचित संदेह से परे साक्ष्य पर जोर दिया है और इसी कारण भारत में भी हम उचित संदेह से परे साक्ष्य पर जोर देते रहे हैं।

33. संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक कानून के एक प्रसिद्ध लेखक, फ्रांसिस व्हार्टन ने अपनी पुस्तक व्हार्टन क्रिमिनल एविडेंस में न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया है, जो इस प्रकार है:-

उचित संदेह वाक्यांश को परिभाषित करना कठिन है। हालाँकि, सभी आपराधिक मामलों में इस शब्द की सावधानीपूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। अक्सर उद्धृत या अनुसरण की जाने वाली परिभाषा मुख्य न्यायाधीश शॉ द्वारा वेबस्टर मामले कॉमनवेल्थ बनाम वेबस्टर⁵ में दी गई है। वे कहते हैं:

"यह केवल संभावित संदेह नहीं है, क्योंकि मानवीय मामलों से संबंधित और नैतिक साक्ष्य पर निर्भर हर चीज किसी न किसी संभावित या काल्पनिक संदेह के लिए खुली रहती है। मामले की वह स्थिति जिसमें सभी साक्ष्यों की पूर्ण तुलना और विचार-विमर्श के बाद भी जूरी सदस्यों के मन में यह विचार रह जाता है कि वे आरोप की सत्यता के बारे में नैतिक रूप से दृढ़ विश्वास नहीं कर सकते।"

34. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशोर गोपाल दास⁶ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उचित संदेह की अवधारणा को संक्षेप में इस प्रकार समझाया है:

"...संभावना की मात्रा और साक्ष्य की मात्रा के मूल्यांकन में एक स्पष्ट व्यक्तिपरक तत्व होता है। अंततः, न्यायिक संभावना एक मजबूत सामान्य ज्ञान और अंततः न्यायाधीश के प्रशिक्षित अंतर्ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। जबकि आपराधिक प्रक्रिया द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई सुरक्षा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए, वहीं साथ ही, तुच्छ बातों का अनभिज्ञ वैधीकरण आपराधिक न्याय प्रशासन का उपहास करेगा।"

35. रमाकांत राय बनाम मदन राय और अन्य⁷ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"24. संदेह तभी उचित कहलाएगा जब वह अमूर्त अटकलों से मुक्त हो। कानून सत्य के अलावा किसी और को प्राथमिकता नहीं दे सकता। उचित संदेह के लिए, उसमें अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। संदेह साक्ष्य से या साक्ष्य के अभाव से उत्पन्न आरोपी व्यक्तियों के अपराध के संबंध में वास्तविक और ठोस संदेह होना चाहिए, न कि केवल अस्पष्ट आशंकाएँ। उचित संदेह काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है; बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है। यह मामले में साक्ष्य से उत्पन्न होना चाहिए।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



36. उपरोक्त निर्णय का हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गोवर्धन एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य⁸ के मामले में अनुसरण किया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

"20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के अनुसार, किसी तथ्य को तब सिद्ध माना जा सकता है जब न्यायालय अपने समक्ष उपस्थित मामलों पर विचार करने के बाद या तो उसके अस्तित्व में विश्वास करता है या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को उस विशेष मामले की परिस्थितियों में उसके अस्तित्व की धारणा पर कार्य करना चाहिए। न्यायालय यह जांच करता है कि आरोपित तथ्यों, जिनमें अभियुक्त पर आरोपित विशेष आपराधिक कृत्य भी शामिल हैं, सिद्ध हुए हैं या नहीं।

21. यह भी ध्यान देने योग्य है कि कानून साक्ष्यों को पुख्ता तरीके से जोड़ने का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि आपराधिक मामले में प्रमाण का मानक सभी संदेहों से परे प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल उचित संदेह से परे प्रमाण है। दूसरे शब्दों में, यदि सभी साक्ष्यों को एक साथ जोड़ने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है जो अपराध को अंजाम देने में आरोपी की भूमिका को संदेह से परे साबित करती है, तो न्यायालय आरोपी को आपराधिक रूप से दोषी ठहराता है और दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उसे दंडित करता है, जो कि दीवानी कार्यवाही के मामले में संभावनाओं की प्रबलता पर आधारित प्रमाण की आवश्यकता से भिन्न है।

22. इस समय यह चर्चा करना प्रासंगिक होगा कि उचित संदेह का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि ऐसा संदेह काल्पनिक अटकलों से मुक्त होना चाहिए। यह सूक्ष्म भावनात्मक विवरणों का परिणाम नहीं होना चाहिए, और संदेह वास्तविक और ठोस होना चाहिए, न कि केवल अस्पष्ट आशंका। उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है, बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है।"

37. जितेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ जितू बनाम मध्य प्रदेश राज्य⁹ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"17. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जहां अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से भिन्न एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, तो अपीलीय न्यायालय को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देने में संकोच नहीं करना चाहिए।"

38. उपरोक्त सभी कारणों से, जब हम मामले के तथ्यों के अनुसार, गवाह संख्या 1 और गवाह संख्या 3 की गवाही का सावधानीपूर्वक और उचित सतर्कता के साथ मूल्यांकन करते हैं, तो हम पाते हैं कि उनकी गवाही दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए हमारे विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। न्यायालयों द्वारा इसे स्थापित कानूनी सिद्धांतों की कसौटी पर परखे बिना, इसे अचूक सत्य मान लेना न्याय का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



39. इस न्यायालय ने वर्तमान आपराधिक अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया है और उपरोक्त निर्णय दिया है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में घटित घटना चार दशक से अधिक पुरानी है। अपीलकर्ता को दिनांक 01.08.1984 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। वर्तमान आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान लगभग 40 वर्षों तक उसे जमानत पर रखा गया है। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता अब अत्यधिक वृद्ध है, जिसकी आयु लगभग 100 वर्ष बताई जाती है।

40. सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपीलों में राहत तय करते समय आपराधिक कार्यवाही की लंबी लंबित अवधि और आरोपी की अधिक उम्र को प्रासंगिक कारकों के रूप में स्वीकार किया है। आपराधिक अपीलों के निपटारे में असाधारण देरी, आरोपी की अधिक उम्र और जमानत पर लंबे समय तक रिहा रहना, राहत तय करते समय एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कारक है।

41. मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामलाल और अन्य¹⁰ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वर्ष 1989 की एक घटना पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि को धारा 304-II भारतीय दंड संहिता में परिवर्तित कर दिया था और आरोपी को पहले से भुगती गई सजा के साथ रिहा कर दिया था, अन्य बातों के अलावा, यह देखते हुए कि प्रथम आरोपी लगभग अस्सी वर्ष का था और अन्य आरोपी सत्तर वर्ष से अधिक आयु के थे। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपील पर तीन दशकों से अधिक समय बाद विचार किया जा रहा था और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आरोपी जमानत पर रहा था।

42. इसी प्रकार, फत्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य¹¹ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि जहां अपीलकर्ताओं ने केवल तीन से चार महीने की सजा काटी है और लगभग 10 वर्षों तक जमानत पर रहे हैं, वहां 10 वर्षों के बाद उन्हें वापस जेल भेजना न्याय के हित में उचित नहीं होगा, और तदनुसार सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक कम कर दिया।

43. हालांकि इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप को संदेह से परे साबित करने में विफलता के कारण दोषसिद्धि को ही गुण-दोष के आधार पर रद्द किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियां - अपील के निपटारे में असाधारण देरी, कई दशकों तक निर्बाध स्वतंत्रता, और अपीलकर्ता की वर्तमान अधिक उम्र - इस निष्कर्ष को और मजबूत करती हैं कि आगे किसी भी प्रकार की हिरासत की सजा देने से कोई लाभ नहीं होगा।

44. तदनुसार, अपील को स्वीकार करते हुए और अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोप से बरी करते हुए, यह पाया गया कि आपराधिक अपील की लंबी लंबितता और अपीलकर्ता की अधिक आयु प्रासंगिक संदर्भ कारक हैं जो इस न्यायालय को किसी भी प्रकार की पुनर्विचार याचिका या दंडात्मक परिणामों को जारी रखने के विरुद्ध प्रेरित करते हैं।

45. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा स्वर्ण सिंह बनाम पंजाब राज्य¹² मामले में दिनांक 22.01.2026 को पारित हालिया निर्णय से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें इसी प्रकार की टिप्पणियाँ की गई थीं। इस मामले की घटना वर्ष 2000 की थी और अपील पर जनवरी 2026 में निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने पाया कि आरोपपत्र के अनुसार, वर्ष 2001 में आरोपी की आयु

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लगभग सत्तर वर्ष थी, और इसलिए, अपील पर विचार के समय उसकी आयु चौरानवे वर्ष से अधिक थी। आगे यह भी दर्ज किया गया कि अपीलकर्ता को पच्चीस वर्षों से अधिक समय तक जांच, मुकदमे और अपील की पीड़ा सहनी पड़ी थी और वह पहले ही छह वर्षों से अधिक का वास्तविक कारावास भुगत चुका था, जिसमें छूट सहित कुल हिरासत अवधि ग्यारह वर्षों से अधिक थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने धारा 304-1 भारतीय दंड संहिता के धतहत दोषसिद्धि में संशोधन करते हुए, अपीलकर्ता की अधिक आयु और लंबे समय के बीतने को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक कम कर दिया है। यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि अत्यधिक वृद्धावस्था और आपराधिक कार्यवाही के निष्कर्ष में अत्यधिक देरी, राहत तय करने में प्रासंगिक कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं।

46. आपराधिक कानून निस्संदेह सामाजिक हित की रक्षा के लिए मौजूद है, लेकिन यह इस मूलभूत आधार पर भी आगे बढ़ता है कि सजा को उसके वैध उद्देश्य, जो निवारण, प्रतिशोध और सुधार हैं, से तर्कसंगत रूप से जुड़ा रहना चाहिए। जहां समय का अंतराल इतना असाधारण रहा हो कि एक आरोपी ने अपने शेष जीवन का अधिकांश भाग लंबित आपराधिक मामले की छाया में बिताया हो, वहां कानून का दंडात्मक कार्य अनिवार्य रूप से अपनी व्यावहारिक और नैतिक शक्ति का बहुत कुछ खो देता है।

47. न्याय मानवीय परिस्थितियों से अछूता कोई अमूर्त विचार नहीं है। कानून बढ़ती उम्र के साथ आने वाली शारीरिक दुर्बलता, निर्भरता और जीवन के सीमित क्षितिज की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर न्यायालय के समक्ष खड़ा होता है, तो दशकों की प्रक्रियात्मक देरी के बाद दंडात्मक परिणामों पर जोर देने से न्याय अपने मूल उद्देश्य से विमुख होकर एक रस्म में तब्दील होने का खतरा रहता है।

48. इतनी लंबी देरी केवल प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। पीढ़ियों तक चलने वाली आपराधिक प्रक्रिया केवल जवाबदेही का साधन नहीं रह जाती, बल्कि स्वयं में ही दंड का स्वरूप धारण कर लेती है। न्याय की वर्तमान आवश्यकताओं का आकलन करते समय दशकों से झेली गई चिंता, अनिश्चितता और सामाजिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

49. निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का संवैधानिक वादा मुकदमे के साथ समाप्त नहीं होता। यह अपील सहित आपराधिक मामले के संपूर्ण जीवन चक्र में व्याप्त है। जब न्याय प्रणाली ही उचित समय सीमा के भीतर अंतिम निर्णय देने में असमर्थ रही हो, तो न्यायालयों द्वारा राहत प्रदान करते समय संयमित और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना उचित है।

50. अंततः, आपराधिक न्याय की वैधता उसके परिणामों की कठोरता में नहीं, बल्कि उनकी नैतिक सुसंगति में निहित है। जहाँ दोष सिद्ध न हो और आरोपी चार दशकों तक अभियोग के बोझ तले दबा रहा हो, वहाँ न्याय, निष्पक्षता और मानवीय गरिमा के अनुरूप एकमात्र परिणाम पूर्ण दोषमुक्ति है, इस सचेत मान्यता के साथ कि लंबे समय तक लंबित रहना और अत्यधिक उम्र किसी भी अवशिष्ट दंडात्मक परिणाम के विरुद्ध कार्य करते हैं।

51. उपरोक्त सभी कारणों से, यह आपराधिक अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



52. हमीरपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.07.1984 को पारित किया गया विवादित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

53. अपीलकर्ता धानी राम उर्फ धनाइयां पहले से ही जमानत पर है। उसकी जमानत रद्द की जाती है।

54. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाए।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति) (चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सौरभ

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"